

बड़ी छलांग के लिए अर्थव्यवस्था को निवेश का बूस्टर डोज

लक्ष्य : एक ट्रिलियन डालर वाला **उत्तर प्रदेश** अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र पर बढ़ा रहा जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो बड़े सपने देखो और उन्हें साकार करो। कुछ इसी सोच के साथ योगी सरकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में एक ट्रिलियन डालर का आकार देने का दुरूह लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। इस कठिन चुनौती से पार पाने के लिए योगी सरकार ने इस साल अर्थव्यवस्था को निवेश की बूस्टर डोज देने का दांव चला है।

अखिलेश सरकार ने आखिरी बजट वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पेश किया था, जो 3,46,934.78 करोड़ रुपये का था। बीती 22 फरवरी को योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया, उसका आकार 6,90,242.43 करोड़ रुपये था। सात वर्षों में बजट का आकार लगभग दोगुना हो गया। जाहिर है कि बड़े बजट को ईंधन देने के लिए राज्य सरकार को अपनी राजस्व प्राप्तियां भी बढ़ानी पड़ीं। बीते छह वर्षों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 89 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि

17 प्रतिशत वृद्धि जीएसडीपी में वालू वर्ष में तो 19 प्रतिशत अगले साल अनुमानित



इंवेस्टर्स समिट में बोलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ • फाइल फोटो

कर राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने कर चोरी पर अंकुश लगाने के साथ कर आधार को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। जीएसटी के अंतर्गत 28 लाख व्यापारियों का पंजीकरण इसकी गवाही दे रहा है। हालांकि इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। मूलतः कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश

ने रोजगार के अवसर सृजित कर अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र पर जोर दिया है। मैनुफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने न सिर्फ विभिन्न सेक्टरों के लिए 25 निवेशोन्मुख नीतियां बनाईं, बल्कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान

राज्य का स्वयं का कर राजस्व	
वर्ष	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रुपये)
2017-18	97,930
2018-19	1,20,121.85
2019-20	1,22,825.83
2020-21	1,19,897.3
2021-22	1,47,367.74
2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान)	1,85,237.98
2023-24 (बजट अनुमान)	2,62,634

देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश जो पहले देश के राज्यों में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, अब गुजरात को पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर आ गया है। देश की अर्थव्यवस्था में उग्र का योगदान आठ प्रतिशत है। महाराष्ट्र पहले और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है।

राज्य का करेतर राजस्व	
वर्ष	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रुपये)
2017-18	19,794.86
2018-19	30,100.71
2019-20	81,705.08
2020-21	11,846.15
2021-22	11,435.97
2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान)	12,294.74
2023-24 (बजट अनुमान)	23,790.77

राज्य में प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भावों पर)

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रुपये)
2017-18	57,944
2018-19	62,350
2019-20	65,677
2020-21	61,374
2021-22	70,792



उग्र का राज्य सकल घरेलू उत्पाद	
वर्ष	जीएसडीपी (करोड़ रुपये)
2017-18	13,78,643
2018-19	14,76,455
2019-20	16,89,871
2020-21	19,40,527
2021-22	18,63,221
2022-23 (पुनरीक्षित अनुमान)	20,48,324
2023-24 (बजट अनुमान)	24,39,171

के तहत 600 से अधिक सुधार कर निवेशकों का दिल जीतने में सफलता पाई। इसके अलावा, सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों के लिए 406 सेवाएं आनलाइन उपलब्ध करवाकर प्रदेश में कारोबार करने में सहूलियत भर माहौल तैयार किया गया। इसी का परिणाम है कि

पिछले माह राजधानी में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को 33.52 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल सके। जानकारों का मानना है कि इन प्रस्तावों के जरिये उग्र को मिलने वाली निवेश की तगड़ी खुराक अपने गुणक प्रभाव से प्रदेश की

अर्थव्यवस्था को लंबी छलांग लगाने का सामर्थ्य देगी। इसी आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में जहां 17.07 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, वहीं 2023-24 में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित है।